

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
- 2.समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग - 1

देहरादून, दिनांक 30 जून 2017

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्यय की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया वर्ष 2017-18 के आय-व्यय की मांगें स्वीकृत होने एवं तत्सम्बन्धी "विनियोग अधिनियम, 2017" पारित होने के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्यय की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग/बजट नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. वित्तीय वर्ष 2017-18 के एक हिस्से हेतु स्वीकृत लेखानुदान की धनराशि को उक्त आय-व्यय में समाहित माना जायेगा।

3. विदित है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्यय में आयोजनागत (Plan) तथा आयोजनेत्तर (Non-Plan) का अन्तर समाप्त कर दिया गया है। साथ ही शासन के व्यय में मित-व्ययता नितान्त आवश्यक है। मित-व्ययता सुनिश्चित करना केवल वित्त विभाग का ही दायित्व नहीं है वरन समस्त प्र0वि0 का भी दायित्व है। धनराशि अवमुक्त करने सम्बन्धी प्रत्येक आदेश, चाहे वह सम्बन्धित वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग की सहमति से निर्गत किया जाये अथवा सीधे प्रशासनिक विभागों अथवा अन्य प्राधिकारियों द्वारा, को तभी निर्गत किया जायेगा जब इस हेतु इन्टरनेट के माध्यम से वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 तथा तदक्रम में समय-समय पर निर्गत अन्य आदेशों के अधीन साफ्टवेयर से केन्द्रीय स्तर पर एक विशिष्ट नम्बर प्राप्त करा लिया जाये। बिना इस विशिष्ट नम्बर के किसी भी आदेश के आधार पर कोई आहरण एवं व्यय नहीं किया जायेगा। विभागाध्यक्ष स्तर पर बजट का आवंटन विभाग में कार्यरत वरिष्ठतम वित्त अधिकारी द्वारा आहरण-वितरण अधिकारी को किया जायेगा। इस

8. **समस्त नये कार्यों** हेतु वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में बहुधा यह देखा गया है कि नये निर्माण कार्यों की स्वीकृति के समय लागत एवं समय वृद्धि (Cost and Time Over run) से बचने के लिए बजट मैनुअल के प्रस्तर-182(VI) (2) एवं (3) की अनुपालना नहीं की जाती है जिसके कारण बजट व्यवस्था के सापेक्ष बड़ी मात्रा में कार्य निर्माणाधीन रहते हैं, क्योंकि प्रारम्भ में कार्य विशेष हेतु न्यून अथवा प्रतीक (Token) धनराशि आधार पर कार्य की स्वीकृति दे दी जाती है और तदोपरान्त अगली किशतों में भी अति न्यून धनराशि अवमुक्त की जाती है। परिणाम स्वरूप कार्य लम्बे समय तक निर्माणाधीन रहते हैं और उपयोग में नहीं लाये जा पाते तथा उनमें लागत वृद्धि की स्थिति भी उत्पन्न होती है। अतः पूर्व स्वीकृत प्रत्येक निर्माण कार्य का नियमित एवं सघन अनुश्रवण व समीक्षा की जाय और जो कार्य किन्हीं कारणोंवश प्रारम्भ नहीं हुए हैं उनकी स्वीकृति निरस्त करते हुए आवश्यकतानुसार उन कार्यों के सम्बन्ध में नये आगणन के आधार पर बजट उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृति पर नये सिरे से विचार किया जाय। इस सम्बन्ध में संलग्न प्रपत्र-1, 2 एवं 3 पर भवनों के निर्माण से सम्बन्धित संकलित सूचना भी वित्त अनुभाग-1 एवं सम्बन्धित वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग को उपलब्ध करा दी जाए एवं साथ ही नये निर्माण कार्यों की स्वीकृति के प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय भी इन सूचनाओं को बी०एम०-80 अन्तर्गत वित्त विभाग की सहमति व उच्च अनुमोदन के साथ प्रस्तुत किया जाय। **बजट मैनुअल के प्रस्तर-182(6)** प्रावधानानुसार नये निर्माण कार्यों/परियोजनाओं का पर्याप्त और समय पर वित्त पोषण सुनिश्चित करने के लिये विभागों को **अनुमानित लागत का न्यूनतम 40 प्रतिशत प्रथम किशत में, 40 प्रतिशत द्वितीय किशत में एवं शेष तृतीय किशत में** प्रदान किये जाने की व्यवस्था है, लेकिन विभागों द्वारा इस नियम का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः **प्र०वि० बजट मैनुअल के प्रस्तर-182(6)** प्रावधानानुसार नये निर्माण कार्यों हेतु धनराशि निर्गत किये जाने के प्रस्ताव तीन चरणों में **40-40-20 प्रतिशत के आधार पर वित्त विभाग को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।**

9. निर्माण कार्यों को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए, जिस हेतु निर्माण की प्राथमिकता और समय सारिणी इस प्रकार तैयार की जाए कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके और पूर्ण होने वाले कार्य शीघ्र पूर्ण होकर उपयोग में लाये जा सकें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करा लिया जायेगा कि प्रत्येक निर्माणाधीन कार्य के सम्बन्ध में **वित्त विभाग के आदेश संख्या-475/XXVII(1)/2008 दिनांक 15.12.2008** के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम०ओ०यू० किया गया है। यदि कार्यदायी संस्था राजकीय विभाग भी हो तो भी समय सारिणी अनुसार कार्य पूर्ण कराने की दृष्टि से निर्धारित प्रारूप पर एम०ओ०यू० किया जाय।

महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। ऐसे मामलों में यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि योजना/निर्माण कार्यों की अनुमोदित कुल लागत की सीमा के अधीन ही धनराशि निर्गत की जाए तथा सक्षम स्तर से अनुमोदित योजना/निर्माण कार्य के अन्तर्गत नियत लक्ष्यों व उद्देश्यों की पूर्ति अनुसार कियान्वयन की प्रगति सुनिश्चित की जाए।

13. **केन्द्रपोषित योजनाओं** के सम्बन्ध में केन्द्रांश की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने पर तथा वित्त अनु०-०१/बजट निदेशालय से पुष्टि कराये जाने के पश्चात् आंवटित बजट की सीमा तक प्रशासकीय विभाग अपने स्तर पर निर्गत कर सकते हैं। राज्यांश की धनराशि से सम्बन्धित प्रस्ताव योजनान्तर्गत केन्द्रांश की सम्पूर्ण धनराशि निर्गत किये जाने के बाद वित्त विभाग को प्रस्तुत किये जायेंगे। **केन्द्रांश की प्रत्याशा में धनराशि किसी भी स्थिति में निर्गत नहीं की जायेगी तथा केन्द्रपोषित योजनाओं से किसी अन्य योजना में पुनर्विनियोग पूर्णतः वर्जित है।**

14. **वाहय सहायतित योजनाओं** के अन्तर्गत प्र०वि० यह सुनिश्चित करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवमुक्त धनराशि का 70 प्रतिशत प्रतिपूर्ति (Rembursment) भारत सरकार से प्राप्त किया जा चुका है एवं तदोपरान्त बजट की सीमा के अन्तर्गत चालू योजनाओं की धनराशि प्रशासकीय विभाग द्वारा स्वयं अवमुक्त किये जायेंगे। नये निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर वित्त विभाग की सहमति से निर्गत की जायेगी। ₹50.00 करोड़ से अधिक EAP को दो समान किस्तों में अवमुक्त किया जायेगा।

15. **एस०पी०ए०** योजना हेतु कुल स्वीकृत धनराशि से अधिक की धनराशि (भारत सरकार व राज्य सरकार) निर्गत नहीं की जायेगी, यदि पूर्व में राज्य द्वारा कुछ धनराशि भारत सरकार से प्राप्ति की प्रत्याशा में निर्गत की गई है और भारत सरकार से धनराशि बाद में प्राप्त हो गई है तो राज्य द्वारा प्रत्याशा में दी गई धनराशि समायोजित कर ली जायेगी और यदि भारत सरकार से धनराशि विलम्ब से प्राप्त हुई है व बजट में प्रावधान न हो पाया हो तो उसके प्रावधान हेतु अगले अनुपूरक बजट में प्रावधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए या अनुदान में उपलब्ध किसी केन्द्र पोषित योजना से पुनर्विनियोग का विचार किया जाए।

16. **एस०पी०ए०(आर०)** के अन्तर्गत बजट प्रावधान आपदा विभाग के अन्तर्गत किया गया है। चूंकि यह एक समयबद्ध संसाधन (Time bound resource) है। अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में भारत सरकार की साईट पर अपलोडेड तथा स्वीकृत परियोजनायें एवं जिस पर भारत सरकार द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है तथा धनराशि अवमुक्त भी कर दी गई है, ऐसे समस्त परियोजनाओं को भारत सरकार के द्वारा जारी धनराशि की सीमा तक वित्तीय स्वीकृति का अधिकार आपदा प्रबन्धन विभाग को दिया जाता है। एस०पी०ए०(आर०)

अनुदान के अधीन धनराशियां जारी की जाय, अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसके लिये सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

20. जैसा कि बजट मैनुअल के प्रस्तर-75 में इंगित किया गया है बजट नियंत्रण अधिकारी या विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो एवं सचिवालय के सम्बन्धित विभाग इस बात को सुनिश्चित करने के उत्तरदायी होंगे कि विभागीय सचिवों/प्रमुख सचिवों के स्तर पर वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी मामले में सीमा से अधिक व्यय अथवा विचलन दृष्टिगोचर हो, तो उसे तत्काल वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाय। कोर ट्रेजरी सिस्टम माध्यम से व्यय का अध्यावधिक विवरण बी0एम0-8 पर प्राप्त करते हुये व्यय की नियमित समीक्षा की जाय। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचनायें समय से भेजा जाना सुनिश्चित करना प्रशासनिक विभाग का उत्तरदायित्व है, जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। प्रशासनिक/बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेखा जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार से मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग-1 तथा बजट निदेशालय को प्रेषित किया जाए। राजस्व मद से पूंजीगत मद में इसी प्रकार पूंजीगत मद से राजस्व मद में पुनर्विनियोग पूर्णतः प्रतिबन्धित है।

21. प्र0वि0 विभागों द्वारा यदि किसी योजनाओं में धनराशि पी0एल0ए0 खाते में जमा की गई है तो सर्वप्रथम उक्त धनराशि को आहरित कर व्यय सुनिश्चित किया जायें। तदोपरान्त ही योजनान्तर्गत आय-व्ययक में स्वीकृत धनराशि अवमुक्त की जायें।

22. वाहन क्रय हेतु कोई व्यय करने से पूर्व राज्य सरकार की नई वाहन नीति के अन्तर्गत ही सुविचारित निर्णय लिया जाय एवं नये वाहन क्रय करने से पूर्व प्रत्येक प्रकरण पर वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

23. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव